International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 721-725

भारत–अमेरिका संबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

Dr. Himanshu Yadav
P.D.F, Department of Political Science, University of Allahabad, Uttar Pradesh, India

प्रस्तावना

नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच दोस्ती की पाइपलाइन बहुत ज्यादा हैं बावजूद इसके कि घरेलू मोर्चे पर इसके न करने वाले बहुत ज्यादा हैं जिन्होनें अपने कौशल को नकारात्मकता के नवाब के मानिंद खड़ा किया है। नई दिल्ली ने अपने आपको इस तरह से साधा है जिसमें वो अपने दक्षिण एशिया के बिल्कुल पड़ोसियों को एकजुट करने के साथ ही रूस और अमेरिका जैसे सुपर स्टेट को भी अपने हितों के मुताबिक बांध दिया है। नई दिल्ली के लिए भारत–अमेरिकी बुलावा एक नयी उम्मीद है जिसमें सभी चीजें निश्चित पीआरसी के दायरे में कही जाती हैं पाकिस्तान का इस्लामी गणराज्य जुड़वा राष्ट्रीयता और उनके जोश के बीच एक आपसी समझ के नतीजे के तौर पर विकसित हुआ है।[1]

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सम्बन्धों एवं संयुक्त समझौतों का सफर

भारत और अमेरिका का 'द्विपक्षीय' रिश्ता एक ऊबड़खाबड़ रास्ते से होकर गुजरा है जिसमें घरेलू कट्टरता की बुदबुदाहट और न कहने वालों के प्रभाव के चलते झटके इसके अभिन्न हिस्से रहे हैं। लगातार नकारात्मकता ने भारत–अमेरिका संबंधों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई है जिसमें तेज गति का समय एक कूटनीतिक प्रकाश के उज्जवल प्रभाव में बदल गया। घरेलू नासमझी के चलते दोनों देशों के बीच सहयोग का रास्ता बहुत कठिन हो गया था।[2]

यह हमेशा अकादमिक और उद्देश्यपूर्ण होगा अगर पवित्रतापूर्ण, समग्र और व्यापक नजरिये के खतरे को समझकर राष्ट्र राजय अभिनेताओं के बीच कोई द्विपक्षीय भागीदार के बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ा जाय। 'भारत–अमेरिका द्विपक्षीय'' सहयोग का समकालीन संदर्भ भी उसी धारणा और आवेग को आगे बढ़ाने की बात करता है। जिसमें एक ठोस सामान्यीकरण है जिसकी पूरी दुनिया में स्वीकार्यता है।

सामान्यीकरण एक रटने और सीमांकित रिसेप्टर के लिए कोष रहा है, लेकिन अनियत तरीके से, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक वैश्विक नियामक मौजूं होता है क्योंकि वह अपने स्वरूप में बहुत व्यापक होता है। यह 'पुरातन और स्थैतिक विधि' नहीं है बल्कि इसका विशाल विस्तार और भारत–अमेरिका रक्षा साझेदारी का महत्व यह है कि वो एक ऐसे जहाज में सवार है जो कायापलट की यात्रा पर है। भारत को पूरी क्षमता के साथ राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट का समर्थन हासिल था जिसने भारत की स्वतंत्रता का आह्वान किया था वह ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्रता नहीं थी। शीतयुद्ध का लड़ाकू समय और 1962 के ध्वसं ने भारत सामरिक विचारों में एक स्मार्ट विचार के तारे के तौर पर सामने आया। चुशूल में मेजर शैतान सिंह के बलिदान ने सबसे ज्यादा जरूरी अमेरिकी सहायता की शुरूआत की जब राष्ट्रपति कैनेडी ने नई दिल्ली से भारतीय वायुसेना को स्टार लड़ाकों से लैस करने की बात कही। तब तक संघर्ष विराम का आदेश दिया गया था और इस मामले को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया औश्र उसके बाद एक मिथकीय इतिहास सामने लाया गया जो तब के एनएएम के महारथियों के लिए फिट बैठता था लेकिन मौजूदा नीति निर्माताओं के लिए आज भी विद्वेष की वजह बना हुआ है। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बाद दोनों देशों को अपने बीच एक स्वस्थ रिश्ते को बनाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसे एक सैद्धांतिक माध्यम से कुछ इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है मसलन जटिल परस्पर निर्भरता के समय में अनिश्चितताओं का समय जिसे प्रोफेसर बीएम जैन ने आगे बढ़ाया था और रौटेलेज ने इसका प्रकाशन किया था। जिसमें मतभेद के बावजूद दो जुड़वा राष्ट्रों का एक दूसरे के करीब आना एक कूटनीतिक प्रयास का नतीजा होता ये राष्ट्र कोई दूसरे नहीं बल्कि भारत और अमेरिका थे।

लेकिन 1995 में जनरल किर्कलाटर की पहल और अब उनका किर्कलाइटर प्रस्ताव और 1993–1994 मतें विलियम पेरी की मजबूत कूटनीतिक पहल कोई मिथन नहीं बल्कि तथ्यात्मक इतिहास का हिस्सा है। जल्द ही इसको आगे बढ़ाने के लिए 1995 में प्रसिद्ध पेंटागन और देश के रक्षा मंत्रालय के बीच संयुक्त विचार–विमर्श के साथ ही निकट भविष्य में सैन्य अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा अनुसंधान और हथियार प्रस्तुतियों में शामिल होने की शुरूआत के जरिये रिश्तों का सिलसिला आगे बढ़ा। फिर भी इस दौर में भी सबसे बड़ी चिंता का विषय ये रहा कि कैसे अमेरिकी खुफिया विभाग संवेदनशील और दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकीयों पर कोई असर नहीं डालेगा।

सामरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट के केन्द्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005 में रक्षा सहयोग के लिए नई रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने अपने रक्षा संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका के सााथ और अधिक वार्षिक सैन्य अभ्यास आयोजित करता है जो किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत ज्यादा है। संचयी रक्षा की बिक्री शून्य से बढ़कर 8 बिलियन डालर हो गई है और बड़े स्तर पर रक्षा मुद्दों पर आदान–प्रदान में बड़ी बढ़ोत्तरी हुई है।[3]

भारत–अमेरिका सामरिक सहयेाग भी जुड़वा राष्ट्र राज्यों के बीच बढ़ते तालमेल को दर्शाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वाणिज्यिक और रक्षा दोनों की सगाई ने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दे दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के गृहमंत्री जॉन केरी और वाणिज्य मंत्री पेन्नी प्रिट्जर ने रिश्ते को 22 सितम्बर 2015 को मजबूत गांठ के साथ बांधा जब वाणिज्यिक

और रक्षा वार्ता के प्राकृतिक संदर्भों में भारत–अमेरिकी कूटनीतिक–रक्षा–राजनयिक रिश्ते पर सरकारी मुहर लगाई।

नई दिल्ली को इस संदर्भ में किए गए अमेरिकी शिकायतें साफ तौर पर दोनों देशों के उद्देश्यों और कार्रवाइयों को बांधने का काम करती हैं जो नैतिकतावाद की छाया और सामरिक अस्पष्टता से प्रणालीगत इंटरफेस के जरिये निजात पा सकता है। विदेश मंत्रालय (एमईए) से जारी एक रिलीज मानती है कि 'अमेरिका की ओर से मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत की सदस्यता के लिए उसके समर्थन की पुष्टि हुई है साथ ही दूसरे वैश्विक अप्रसार निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भी उसका समर्थन हासिल है।

बहु भूमिका वाले लड़ाकू सेनानियों की शर्त गड़बड़ा जाने के अलाव गुलाबी टुकड़े सी–130 हरकुलिस यातायात विमान के तौर पर सामने आए जिसमें वाशिंगटन के साथ सामग्रीगत समर्थन का समझौता भी शामिल था जिससे पीआईसी को बांधा जा सके और एशिया प्रशांत क्षेत्र में एकता को बनाए रखा जाए। एक सीधे दीवार से दृष्टिकोण आगे हमें सूचित करेगा कि अमेरिका के नेतृत्व में समुद्री अभियान को फिर से संयोजित किया जा सकता है जिसका बड़ा लाभ नई दिल्ली को होगा।

हालांकि पीआरसी की रोकथाम एक घोषित भारतीय और अमेरिकी चिंता का विषय नहीं होना चाएिह लेकिन सहयोगी प्रतिस्पर्धी चिंता द्विपक्षीय स्तर पर समुद्री जगह के प्रबंधन से जुड़ी हुई है। यह सब अंतर्राष्ट्रीय कहानी के अविश्वास जैसा है जो सत्यता में घुसी हुई है और वैश्विक सबक है। 'परमाणु दायित्व' एक दोनों देशों के बीच एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है लेकिन उसे दोनों कारगर तरीके से हल करने की क्षमता रखते हैं। सौदा हो गया है। दीर्घ प्रतिक्षित परमाणु समझौता हो गया है जिसे ओबामा–मोदी ने जनवरी 26, 2016 में अंतिम रूप दिया।[4]

साार्वजनिक और फोटो सत्र कूटनीति वाशिंगटन के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहलः चित्रण एक ललित चित्रण है.. एक तरह से यह एक मिथक है कि दोनों राष्ट्र एक गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। और यह केवल सार्वजनिक कूटनीति के माध्यम से नहीं है। निर्माण में मिथक फोटो और खुशमिजाजी का भी हाथ है जिसमें नयी निकटता को फोटो खिंचवाने में भी व्यक्त किया।

इस तरह के अवसर कम काल्पनिक और अधिक प्रतिबिंबित दिखाई पड़ता है जिसमें भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा और उत्साह का अत्यधिक तालमेल है। व्यक्तित्व कारक राजनयिक अध्ययन के क्षेत्र में प्रचलित दोनों राज्य प्रमुखों की अंतरंगता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कथा पर एक बैनर बनता है जो सहकारी मिश्रण का व्यक्तिगत प्रकृति द्वारा एक सटीक वर्णन मिलता है। 'फोटो–ऑप्स' किसी भी कूटनीतिक पहल से बहुत ज्यादा कुछ तत्व समेटे होताा है जिसके लिए दो प्रमुख राष्ट्रों के मुखिया एक साथ खड़े होते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 'मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका का सितंबर 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दौरा किया। इस यात्रा में भारत और अमेरिका ने कई चीजों पर केंद्रित करने के बारे में फैसला लिया इसमें अफगानिस्तान, सीरिया और इराक में विकास भी शामिल था। दोनों नेता बैठक के दौरान एक दूसरे से बात करते हुए देखे[5] गए। एक और घटना उस समय सामने आई जब राष्ट्रपति ओबामा ने जनवरी 2016 में नई दिल्ली का दौरा किया और गणतंत्र दिवस समारोज के बाद चाय पर चर्चा के दौरान दोनों एक बार फिर अनौपचारिक तरीके से बात करते देखे गए। अखबार के अंश आगे कहता है–'जनवरी 2015 में जब ओबामा ने भारत का दौरा किया प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रोटोकाल तोड़कर हवाई अड्डे पर ओबामा का स्वागत करने गए। एक फोटो में मोदी और ओबामा हैदराबाद हाउस के गार्डेन में चाय के दौरान हंसते देखे गए।[6]

तथ्य यह है कि खेल कूटनीति, सांस्कृतिक कूटनीति की तरह अब फोटो–ऑप कूटनीति रिश्तों को विकसित करने का नया माध्यम है ये बातचीत में शामिल दोनों सरकारों के लिए आशावाद के नये रास्ते को खोलता है। अपने राष्ट्रपति अवधि के प्रारंभ में, राष्ट्रपति ओबामा ने एक उदाहरण के रूप में अमेरिकी कांग्रेस में एक सामान्य विधेयक पर गतिरोध को घरेलू सार्वजनिक कूटनीति के जरिये खत्म कर दिया। इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों से साझेदारी और बातचीत का रास्ता अपनाया।

अमेरिकी राष्ट्रीय अटलांटिक का सार्वजनिक और फोटो अप कूटनीति से हासिल होने के बारे में कहा है कि 'व्हाइट हाउस के प्रेस सविच जे कार्नी ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति ओबामा तीन सीनेटरों के साथ गोल्फ गए थे' इस सिद्धांत की परीक्षा के लिए कि क्या इससे जो कुछ लोग परिणा चाहते हैं वो मिल पाएगा। यह अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ओबामा कांग्रेस से जो हासिल करना चाहते हैं इसके जरिये मिल सकता है। जब इस विचार पर काम चल रहा हो तो लोग इस तरह कोई सुझाव देना बंद कर देंगे अगर कोई उस पर प्रयास कर रहा है।'

अपने वैश्विक दौरे एक मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मैनहट्टन में रूके जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया फिर उसके बाद मेडिसन स्क्वैर पर भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति भारतीय झुकाव और अधिक अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारतीय कूटनीति के लंबे इतिहास में कुछ इस तरह के महत्वपूर्ण पल रहे हैं लेकिन खुली बांहों से अमेरिकियों के लिए निवेश के आमंत्रण ने इसको नये चरण में पहुंचा दिया है। एक सरकारी पोर्टल ने राष्ट्रपति ओबामा के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का नये बंधनों में बंधने का प्रयास को भारत और अमेरिका रिश्तों की 21वीं सदी में एक निर्णायक मौका करार दिया है।

मोदी जी ने स्वाभिमान के नये तेवर के साथ इसको जाहिर किया 'अमेरिका दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है दुनिया भर से लोग आए हैं और अमेरिका में बसे हैं और भारतीय भी दुनिया के विभिन्न भागों में बसे हैं। वहां कोई ऐसा शहर नही है जहां किसी दूसरी राष्ट्रीयता के लोगों से आपका सामना न हो। इस तरह की समानता प्यारे भाइयों और बहनों मैं विश्वास करता हूं कि केवल सरकार अकेले विकास नहीं कर सकती है।'

उन्होंने आगे अपनी ऊंची भावनाओं और मैडिसन स्कवायर गार्डन में युवाओं की धारा जहां वह जीवंतता और दम है और न्यूयार्क के शहर में जो व्याप्त है उसकी 'बिजली' के साथ वो भरा जा रहा है उसके साथ ही अपने समकालीन अनुभव को जोर देकर रखने7 के जरिये उन्होंने नुक्कड़ पर भारत–अमेरिका संबंधों का नया इतिहास लिखा। नई दिल्ली में अपनी सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं को सामने रखते हुए मोदी के लिए शौचालय और उसके बीच संतुलन बनाना बहुत

कठिन हो रहा था। मेक इन इंडिया ने मेडिसन स्क्वैर पर जुटे युवाओं के लिए राग गान का एक नया गीत बन गया था।

इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि अमेरिकी युवाओं ने भारत को एक बड़े फलक पर लिया। पूरा इवेंट मैनेजमेंट का अभ्यास केवल इवेंट मैनेजमेंट नहीं था जिसने दुनिया को नये विश्व गुरू से परिचित कराया जिसमें शानदार तरीके से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के खात्मे का संदेश भी शामिल था। जिस तरह भीषण शीतयुद्ध के दिनों के बाद नया अमेरिका बनकर सामने आया उसी तरह से भारत एक महान शक्ति के तौर पर सामने आने के लिए तैयार है।

भाषण के दूसरे खं डमें पीआईबी ने बताया कि पी.एम. मोदी ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में क्या दलील दी 'कुछ साल पहले मैं ताइवान का गया था। उस समय मैं न तो प्रधानमंत्री था और न ही मुख्यमंत्री। एक दुभाषिया मेरे साथ किया गया था। हम कुछ दिनों के एक दूसरे के साथ खर्च करके एक दूसरे से परिचित हो गए थे। एक दिन उसने मुझसे पूछा, 'तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा पूछिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन वह अब भी आशांकित और संकोच किए जा रहा था। फिर उसने कहा कि मैंने सुना है कि भारत में लोग काला जादू का अभ्यास करते हैं। वह सांप और सपेरों का देश है। लोग अब भी उन्हें देखते हैं? ऐसा है क्या? मैंने कहा नही। हमारे देश में बहुत अवमूल्यन आया है। हमारे पूर्वज सांपों के साथ खेलते थे, जबकि हम माउस के साथ खेल रहे हैं। हमारे युवा अपने माउस की एक क्लिक के साथ दुनिया को हिला रहे हैं।

'भारत के प्रधानमंत्री समय के बदलते रूख के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो एशिया में एक अगुवा के तौर पर भारत को खड़ा करना चाहते हैं जो एक और अपने किस्म का अमेरिकी सामरिक नीति का हिस्सा है। भारतीय अमेरिकी सपने के विचार और 'चीनी अन्तर' के लिए समान वृद्धि को ध्यान में रखा जाना है। भारत एलपीजी कटौती के दिन और गोल्ड रिजर्व के सदमें से बाहर आ रहा है और उसके साथ ही बहुत लंबा सफर तय कर लिया है जिसमें भूआर्थिक नीति में बड़े स्तर पर बदलाव आया है। खासकर भारत–अमेरिका व्यापार के अर्थशास्त्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है जो अब तकरीबन 500 बिलियन डालर के पार चला गया है जो अपने आप में भारत–अमेरिकी रिश्तों की मजबूती का प्रमाण है।

भारत–अमेरिका सहयेाग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और नरेन्द्र मोदी के संदर्भ में–

'डोनाल्ड ट्रम्प की दुनिया देखने के लिए नजरिया अलग संसुगत रूप में जैसा कि आलोचकों ने उल्लेख किया है, 19वीं सदी के पृथकतावाद के रूप के समान है। परमीत पाल चौधरी, एक प्रख्यात विदेशी मामलों के विशेषज्ञ कहते हैं कि विदेश नीति टीम जिसे वह बना रहे हैं, का भी एक वैश्विक नजरिया है जिसमें एक मजबूत सैन्य, सहयोगी दलों की प्राथमिकता जो कि सुरक्षा बोझ साझा करते हों और एक दुश्मन सूची जिसमें इस्लामी राज्य औरचीन' सबसे ऊपर शामिल हों।

चौधरी राजनीतिक में एक लेख की चर्चा करते हुए कहते हैं, ट्रम्पिज्म में उनके ये विचार में शामिल है कि अमेरिका के सहयोगी दल सुरक्षा जो यह प्रदान करता है उसका लाभ तो लेते है, लेकिन अंकल सैम के लिए बिल या भुगतान छोड़ देते हैं। ट्रम्प कहते हैं, 'बिना कुछ लिए धनी देशों की रक्षा के लिए दुनिया भर में हमारी हंसी उड़ायी जाती है। हमारे सहयोगी 'अरबों बना रहे हैं हमें उपयोग करके। चौधरी कहते हैं कि, ट्रम्प की विदेश नीति अपने चुनाव थीम 'अमरिका पहलें' के आसपास आधारित होने की संभावना है। जर्मन मार्शल फंड के डेनियल ट्विनिंग हवाला देते हुए चौधरी कहते हैं कि ट्रम्प 'दृढ़ता से बराक ओबामा की तुलना में दोनों चीन और पाकिस्तान पर एक मुश्किल रास्ता अपनायेंगे, जो अधिक इसराइल समर्थक होगा और आईएसआई से लडेंगे। 'एशिया धुरी' का ट्रम्प का दृष्टिकोण युद्धपोतों पर बड़ा है, लेकिन चीन को विवश करने के लिए व्यापार के उपयोग के खिलाफ है। ट्रम्प के सलाहकार कि, अमेरिकी नौसेना में 10 युद्धपोतों जोड़ने, जापान और यहां तक कि ताइवान से सैन्य खर्च में वृद्धि करने के आग्रह करने के बारे मतें लिखते है, लेकिन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप छोड़ने के बारे में भी लिखे है। अमेरिका एक हार्ड लाइन दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना चाहता है लेकिन लागत साझा करने के लिए दूसरों को कहना चाहता है।

नीति और राजनीतिक चुनौतियां भी दुनिया के दोनों लोकतंत्रों के बीच घनिष्ठ संबन्धों में बाधा कर सकते है। दोनेां के बीच बेहतर संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए दोनेां को ध्यान देने की जरूरत है। चार मुख्य मुद्दे हैं जिनका बारीकी से नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत निरीक्षण करने की जरूरत है– पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध, भारत की आईटी के साथ भविष्य में अमेरिकी संबंधों और दवा उद्योग, आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका का नजरिया औश्र लम्बित भारतीय विश्वास की कमी जिसका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की 'पिछले रिकार्ड को देखते हुए 1998 के प्रतिबंधों के कारण है, एक सैन्य भागीदार के रूप में विश्वसनीयता है।

नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत अमेरिका–पाकिस्तान संबंधों को अब निरीक्षण करना दिलचस्प होगा क्योंकि पाकिस्तान को पिछले आठ वर्षो के दौरान ओबामा प्रशासन के तहत अमेरिका से 13 अरब डॉलर की सहायता प्राप्त हुई है क्योंकि इसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ गैर राज्यीय अभिनेताओं के लिए समर्थन जारी रखने में उसका हौसला बढ़ाया है।

भारत अमेरिका से पाकिस्तान को सभी प्रकार की सैन्य सहातया रूकवाना चाहता है और साथ ही भारत अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'आतेकवादियों राज्य' घोषित करने में मदद चाहता है। उड़ी हमले के बाद की अवधि में भारत कश्मीर घाटी में और पाकिस्तान के साथ वार्ता गतिरोध के अंत की बहाली पसंद करेगा क्योंकि काफी दिनों से कश्मीर में स्थिति सामान्यीकृत नहीं हो पायी है। राष्ट्रपति ट्रम्प से पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ कठिन निर्णय लेने की उम्मीद है जिससे भारत–अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी में निरंतरता प्रदान होती रहे।[7]

ट्रम्प के तहत भारतीय आईटी और दवा उद्योग के साथ अमेरिका के संबंधों से दोनों देशों के बीच बेहतर रिस्तों के निर्माण की उम्मीद है और सख्त श्रम लागू न करने की सम्भावना है जिसका ि कवह अपने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था जिसने आईटी और दवा कारोबार क्षेत्र में बहुत सी आशंकाओं को जन्म दिया था। उनकी जीत भाषण में ट्रम्प ने किसी भ देश के बारे में विशेष रूप से बात नहीं की। ट्रम्प ने कहा, बहुत ईमानदारी से मुझे लगता कि अब अमेरिका को विभाजन के घाव टारने चाहिए और एक साथ चलने का समय

है। सभी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट और यह देश भर में निर्दलीय के लिए, मै कहन चाहता हूँ कि यह हमें एक यूनाइटेड लोगों के रूप में एक साथ आने का समय है।

यह माना जा रहा था कि ट्रम्प ने बहुत मुश्किल अभियन चलाया था कि वह चीन और भारत से अमेरिका को वापस नौकरियों लाएंगे। ट्रम्प ने राष्ट्रपति ओबामा के स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की बहुत आलोचना की थी। उन्होंने खुले तौरपर ओबामा के प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम को बन्द करने के लिए कहा था[8] जिसके लिए कई भारतीय दवा कंपनियों अमेरिका के लिए सस्ती जेनेरिक दवाओं का निर्यात करती है। आशंका तो है लेकिन ट्रम्प ऐसी बातों को करेंगे ये देखने के लिए तो इंतजार करना होगा।

आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिकी स्टैंड राष्ट्रपति ट्रम्प के तहत बहुत कठिन होने की उम्मीद है। उनके एक इसराइल समर्थक देश होने की उम्मीद है और आईएस जैसे आतंकवादियें संगठनों के खिलाफ माना जाता है। पाकिस्तान का तनव का सामना करना पड़ सकता है। भारत–अमेरिका के सम्बन्धों का एक अन्य पहलू उनके बीच हासिल किया गया 'आतंकवाद विरोधी सहयोग' की प्रतिबद्धता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आतंकवाद के विरूद्ध सहयोग को अपने द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख घटक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को उम्मीद है कि अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने, अलकायदा और आइ.एस.एल जैसे आतंकवादी समूहों को नष्ट करने के लिए एक वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जारी रखने की बहुत उम्मीद करता है।

अमरीकी और भारतीय नेताओं ने, आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने, आतंकवादी नेटवर्क और उनके वित्तपोषण में खलल डालने, और उनके सीमापार से आंदोलन को रोकने के लिए बात की है। पठानकोट में भारतीय एयरबेस पर और जम्मू–कश्मीर में उरी में भारतीय सेना शिविर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले के बाद उनके नेताओं ने भी इस आवश्यकता को माना कि लश्कर, जैश–ए–मुहम्मद (जे.ई.एम.), डी कंपनी और हक्कानी नेटवर्क की तरह के संस्थाओं को कमजोर करने और खलल डालने के लिए संयुक्त और ठोस प्रयासों की जरूरत है। सीमा पार पाकिस्तान की ओर से संचालित इस तरह के आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव लागू करने में भारत के साथ अमेरिका दृढ़ता से खड़ा हो गया है। अमेरिका भी गैर राज्य अभिनेताओं के साथ उनकी मिलीभगत पर पाकिस्तान को एफ–16 लड़ाकू विमानों की बिक्री को रोक दिया है।

सामरिक और वाणिज्य वार्ता 2016 की मुख्य विशेषताएँ

राजनयिक सहयोग

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने आज और अधिक बारीकी से अपने सामरिक दृष्टिकोण, कूटनीतिक प्रशिक्षण, और दुनिया भर में अपने रिस्तों के सरेखित लक्ष्य के साथ राज्य के विभाग और विदेश मंत्रालय के बीच एक नई कूटनीति साझेदारी की घोषणा की। यह संस्थान के कर्मचारियें और राजनयिकों द्वारा साइट यात्राओं के माध्यम से और कूटनीतिक प्रशिक्षण मतें सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान और मजबूती देने और क्षेत्रीय और कार्यात्मक कूटनीतिक मुद्दों की पूरी रेंज पर अपने विचार–विमर्श का विस्तार से एक दूसरे के साथ दोनों पक्षों के 'राजनयिक लोगों को मदद मिलेगी।

रक्षा सहयोग

पिछले कुछ वर्षों में, अमेरिका ने भारत के लिए 10 अरब डॉलर से अधिक रक्षा बिक्री के हस्ताक्षर किए है। इन क्षमताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के मजबूत प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत किया है। उदाहरण के लिए, भारत की वायु सेना ने अप्रैल, 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद यमन से भारतीय और तीसरे देश के नागरिकों खाली करने के लिए और नेपाल को त्वरित राहत सामग्री पहुँचाने के लिए अमेरिकी निर्मित सी–130 और सी–17 विमानों का इस्तेमाल किया। अमरीकी और भारतीय कारोबार, रक्षा उपकरणेां के सह–विकासा, एक बेस की स्थापना जहाँ से भविष्य में नई रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल, सह–भागीदारी और सह उत्पादन की शुरूआत की जा सके, और भारतीय रक्षा प्रौद्योगिक आधार का विस्तार किया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने जून 2015 में एक नए सिरे से 10 साल के रक्षा फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए, नया ढांचा, उच्च स्तर रणनीतिक विचार विमर्श के लिए, दोनेां देशों के सशस्त्र बलों के बीच आदान–प्रदान, और क्षमताओं को मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करता है।

निष्कर्ष

सबसे महत्वपूर्ण विकास है कि अमेरिका ने रूस और इसराइल दोनेां को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गया है जो कई वर्षो, से भारत के दो शीर्ष रक्षा आपूर्तिकता बने हुये थे, और अब तक लगभग 13.6 अरब डॉलर के अमेरिका के साथ हथियार सौदे किये गये है और मौजूदा रूझान से लग रहा है कि आने वाले वर्षों में वे कई बार विस्तार करने की तैयारी में है। संयुक्त राज्य अमरीका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, नागरिक–परमाणु सहयोग, जलवायु परिवर्तन और कई अन्य क्षेत्रों में विस्तार करा जारी है। हाल ही में चीन में जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बैठक के आयोजन सामरिक और अमरीकी राज्य सचिव जॉन केरी और भारतीय मंत्रियों सुषमा स्वराज, सीतारमन और सुरेश गोयल के बीच पहले की वाणिज्यिक वार्ता का परिणाम है।

अमेरिका–भारत रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता 2016 के परिणाम इस वर्ष की सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता की उद्घाटन बैठक, वैश्विक मुद्दों पर उस रिश्ते के विकास और करीबी सहयोग को दर्शाती है। अमेरिका–भारत सहयोग, जिसे राष्ट्रपति ओबामा ने 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारी, का आह्वान किया है आज मानव प्रयास के लगभग हर क्षेत्र में, और वैश्विक कॉमन्स में, दुनिया की लंबाई तक फैला है।

संदर्भ

1. Farred Zakaria. The Post American World and the Rise of the Rest, WW Norton and Company, 2008, 10-30.
2. Richard Lugar. Opening Statement for Hearing on India nuclear Agreement, 2, URL:http//foreign.senate.gov/testimorny/2005/Lugar Statement051102, Accessed, 2005-2016.
3. As Obama Arrives, US Bids for heavy arms business, URL: http://www.rediff.com/news/special/obama-visit-special-as-arrives-us-bids-for-heavy-arms-business/20101105.htm. Online: Web, Accessed, 2016.

4. BM Jain. Indo-US Relations in the Age of Uncertainty: A Uneasy Courtship, Routledge, 2016, 1-8.
5. Centre for Strategic and International Studies. URL: http://www.csis.org/programs/wadhwani-chair-us-india-policy-studies/past -india-chair-projects/us-india-security-and Online: Web, Accssed, 2016.
6. Sushasini Haider. N Deal Logjan cleared: Modi, Obama agree not to dilute Liabiltiy Law, The Hindu, 2016.
7. Kalyan Subramani, Anirban Ghoshal. After victory speech, I.T. firms hope Trump will build bridges, Hindustan Times Jalandhar, 2016.
8. Parmit Pal Chaudhary. Will Trump change uS foreign policy?', Hindustan Times Jalandhar, 2016.